भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5069

जिसका उत्तर 02 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

कोयला आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करना

5069. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश भर में कोयला आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) पहल के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ग) उक्त परियोजनाओं की अनुमानित कुल क्षमता कितनी है;

(घ) क्या रेल-सी-रेल (आरएसआर) पहल से कोयले की ढुलाई में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : एक लचीली और लागत प्रभावी कोयला निकासी संभार तंत्र प्रणाली स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं;

i. **कोयला संभारतंत्र योजना और नीति** कोयला मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2024 में आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ाने, लागत को कम करने और संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई।

ii. खानों से प्रेषण बिंदुओं तक कोयला निकासी की दक्षता बढ़ाने के लिए **फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं का विकास।** ये परियोजनाएं यंत्रीकृत कोयला लदान अवसंरचना को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जैसे कि प्रणाली को अधिक लागत प्रभावी बनाने के लिए न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ कन्वेयर बेल्ट, और क्रशर्स।

iii. कोयले की सुचारू और तेजी से निकासी सुनिश्चित करने के लिए **रेल नेटवर्क के विस्तार** हेतु रेल अवसंरचना में सुधार।

iv. देश में कोयला परिवहन आवाजाही को आसान बनाने के लिए विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों के पास स्थित विद्युत संयंत्रों और उद्योगों के लिए कोयला निकासी हेतु रेल या सड़क के वैकल्पिक मार्ग के रूप **में रेल-सी रेल मोड का उपयोग।**

(ख) और (ग) : कोयला कंपनियों द्वारा 386 मिलियन टन की कुल क्षमता वाली 39 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

(घ) और (ङ) : पिछले दो वर्षों के दौरान, रेल-सी-रेल मार्ग के माध्यम से कोयले की आवाजाही वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 28 मिलियन टन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 54 मिलियन टन हो गई है।

****